of the West Bengal Legislative Council from 1962 to 1968 and was a Minister in the West Bengal Government in 1967. He was first elected to this House in April 1978. He was serving his second term as a Member of this House from April, 1984, when the cruel hand of fate snatched him away from our midst on 27th October. An affable and suave person, Shri Chakraborty made valuable contribution to the deliberations of the House.

Shri Benoy Kumar Mohanti was born at Village Anandpur in the Cuttack district of Orissa State in 1933 and got his higher education at S.K. Academy, Jagatsinghpur, Ravenshaw College and M.S. Law College, Cuttack. A veteran trade unionist, he was deeply engaged in the welfare of labour and other backward sections of society and was associated with several welfare organisations. During his membership of the Rajya Sabha for two terms from April, 1964 to April, 1976, Shri Mohanti took keen interest in the proceedings of the House.

We deeply mourn the passing away of Shri Shankarlal Tiwari, Shri Amarprosad Chakraborty and Shri Benoy Kumar Mohanti. I request Members to rise in their places and observe a minute's silence as a mark of respect to the memory of the departed.

[*Hon. Members then stood in silence for one minute*]

MR. CHAIRMAN: Secretary General will convey to the members of the bereaved families our sense of profound sorrow and deep sympathy.

INTRODUCTION OF MINISTERS

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): Mr. Chairman, I have great pleasure to introduce to you and through you to the House my colleagues who have been appointed as Ministers:

Shri Narayan Datt Tiwari—Minister of Industry.

Shri M. Arunachalam—Minister of State in the Department of Indudstrial Development.

Shri Sitaram Kesri—Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Indian Judical Service

*1. SHRI SYED AHMED HASHMI: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to constitute the Indian Judical Service ;

(b) if so, what were the recommendations made in this regard at the conference of Law Ministers and Chief Justices of various States held in August, 1985 in Delhi; and

(c) by when the proposed service is likely to come into existence ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H.R. BHARDWAJ) (a) to (c) The proposal to constitute an All India Judicial Service is still engaging the attention of the Government, and it is not possible to indicate the time by which the Service would be constituted. The matter was not discussed in the Conference of Chief Justices, Chief Ministers and Law Ministers of States held on 31st August and September 1, 1985.

श्री सैयद अहमद हाशमी : मैंने भी, जो स्टेटमेंट मेरे पास है उसमें इस बात को स्पेसिफाई नहीं किया था कि आल इंडिया जुडिशियल सर्विस के कायम करने का कोई फैसला नहीं किया गया है या इसके अंदर डेलीबिरेशंस नहीं हुई हैं ।

जब यह सवाल पूछा था तो यह समझता था कि जवाब पूरा नहीं किया गया है । अभी ला मिनिस्टर साहब ने यह जवाब दिया है कि अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है । लेकिन जो स्टेटमेंट दी गई है इससे यह अंदाजा जरूर होता है कि हुकूमत के सामने डैलीबिरेशंस है और अंग्रेजों के जमाने के पैटर्न के ऊपर जिस तरीके से हमारे यहां आज जुडिशियल सिस्टम नफाज है इससे अंदाजा यह होता है कि कुछ न कुछ डेलीबिरेशंस हैं और इस पर गौर करने की चिंता या फिक्र है लेकिन इस सिलसिले में मैं यह बात कहूंगा कि यह जरूर है कि डेलीबिरेशंस हैं, आपने कहा है :

"The legislative and administrative.....touching the life of the citizens of all levels...."

इससे यह अंदाजा होता है कि अब तक जो कोर्ट का कम्पोजिशन है या जो कोर्ट का हमारे सामने इजहार होता था उसके अंदर जो रोजमर्रा की जिन्दगी है आवाम की, जनता की . . . (व्यवधान)

†[شری سید احمد هاشمی : میں نے بھی - جو اسٹیٹ میںٹ میرے پاس ہے اسمیں اس بات کو اسپیسیفائی نہیں کیا تھا کہ آل انڈیا جوڈیشیل سروس کے قائم کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے یا اس کے اندر ڈیلیبریشنس نہیں ہوئی ہے - جب یہ سوال پوچھا تھا تو یہ سمجھا تھا کہ جواب پورا نہیں کیا ہے - ابھی لا منسٹر صاحب نے یہ جواب دیا ہے کہ ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن جو اسٹیٹ میںٹ دی گئی ہے اس سے یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ حکومت کے سامنے ڈیلیبریشنس ہیں اور انگریزوں کے زمانہ کے پیٹرن کے اوپر جس طریقہ سے ہمارے یہاں آج جوڈیشیل سسٹم نافذ ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈیلیبریشنس ہیں اور اس پر غور کرنے کی چلتا یا فکر ہے لیکن اس سلسلے میں میں یہ بات کہونگا کہ یہ ضرور ہے کہ ڈیلیبریشنس کی ہیں آپنے کہا ہے :

"The legislative and administrative.... touching the life of the citizens of all levels...."

اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپنگ جو کورٹ کا کمپوزیشن ہے یا جو کورٹ کا ہمارے سامنے جو اظہار ہوتا تھا اس کے اندر جو روزمرہ کی زندگی ہے عوام کی - چلتا کی . . . (مداخلت)]

श्री सैयद अहमद हाशमी : शायद हमारी जुडिशियरी उससे इतनी दूर थी कि उनके जो सही जज्बात जिसको वे जस्टिफाइ कर सकें, उनके सामने नहीं आते । जैसे पहले गांव पंचायतों का जमाना था, तो उनमें लोकल सोसायटी के लोग ही उस मसले में चाहे वह क्रिमिनल हो या दीवानी हो, उसके अन्दर पड़कर उसका फैसला करते थे और लोग मुतमईन भी हो जाते थे ।

†[شری سید احمد هاشمی : شاید ہماری جوڈیشری اس سے اتنی دور تھی کہ انکے جو صحیح جذبات جسکو وہ جسٹیفائی کر سکیں انکے سامنے نہیں آئے - جیسے پہلے گاؤں پنچایت کا زمانہ تھا تو ان میں لوکل سوسائٹی کے لوگ ہی اس مسئلہ میں جاتے وہ کرمنل ہو یا دیوانی ہو اس کے اندر پڑ کر اس کا فیصلہ کرتے تھے اور لوگ مطمئن بھی ہو جاتے تھے -]

MR. CHAIRMAN : Your time is up.

श्री सैयद अहमद हाशमी : मैं सवाल कर रहा हूं । यह बहुत पेचीदा मसला है । आपने यह तो बता दिया कि उसको सिम्पलीफाई करेंगे, लेकिन हिन्दुस्तान में ऐसे गरीब लोग हैं जो कि कोर्ट में पहुंच ही नहीं सकते । मैं समझता हूं कि

†[ ] Transliteration in Arabic script.

सिर्फ लीड लीगल एड देना ही काफी नहीं है, हमारे यहां जो इस समय करप्शन है, उसकी लपेट में क्या वह नहीं आ जाएंगे ? मुझे माफ कीजिएगा, हम जुडिशियरी को उससे अलग नहीं कर सकते। लीगल एड का जो कंसेप्शन है, हम नहीं कह सकते कि उसके अन्दर भी रिश्वत का बाजार गर्म नहीं हो जाएगा ।

†[شری سید احمد هاشمی : میں

سوال کر رہا ہوں - یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے آپ نے یہ تو بتا دیا کہ سمپلی فائی کریںگے لیکن ہندوستان میں ایسے غریب لوگ ہیں جو کہ کورٹ میں پہنچ ہی نہیں سکتے - میں سمجھتا ہوں کہ صرف لیڈ لیگل ایڈ دینا ہی کافی نہیں ہے - ہمارے یہاں جو اس وقت کرپشن ہے اس کی لپیٹ میں کیا وہ نہیں آئینگے - سچے معاف کیجئے گا ہم جوڈیشری کو اس سے الگ نہیں کر سکتے - لیگل ایڈ کا جو کنسیپشن ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر بھی رشوت کا بازار گرم نہیں ہو جائیگا -]

MR. CHAIRMAN: Your two minutes are over now. The Minister will reply now. You will have your second supplementary. You are not putting any supplementary.

श्री सैयद अहमद हाशमी : मैं अर्ज कर रहा हूं कि जिस सोसायटी में हम रहते हैं उसमें ज्यादा लोग गरीब हैं . . .

†[شری سید احمد هاشمی : میں

عرض کر رہا ہوں کہ جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں زیادہ لوگ غریب ہیں -]

MR. CHAIRMAN : The Minister will reply now. If you cannot put a supplementary in two minutes, I cannot help.

†[ ] Transliteration in Arabic script.

श्री हंसराज भारद्वाज : जनाबे वाला, जहां तक आल इंडिया जुडिशल सर्विस का सवाल है, यह मैं अर्ज कर चुका हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने के खिलाफ नहीं है । लेकिन जैसा मेरे लायक दोस्त को मालूम है, जुडिशियरी के मामले में हमको स्टेट गवर्नमेंट से भी राय लेनी पड़ती है और चीफ जस्टिसेज की भी राय लेनी पड़ती है । चीफ जस्टिसेज की राय बड़े माने रखती है । तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि यह मामला जेरे गौर है । ज्यों ही इस पर चीफ जस्टिसेज की राय एकमत हो कर आ जाएगी, यूनेनिमिटी उसमें आ जाएगी, हम उसको इनैक्ट कर देंगे ।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 13 राज्य सरकारों ने इसकी हिमायत की थी और 8 सरकारों ने इसकी मुखालिफत की थी। उसके बाद चीफ जस्टिसेज मिले । उन्होंने 1985 में कहा कि जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए । तो हमने उसका ऐहतराम करके यह फैसला किया है कि जब तक यूनेनिमिटी नहीं आ सके, तब तक हम इस पर कोई फैसला नहीं करेंगे । मैं इस बात का ऐहतराम करता हूं कि जैसा आपने कहा, जुडिशल सर्विस आल इंडिया बेसिस पर होनी चाहिए । हम इसके हक में हैं । लेकिन हम चाहते हैं कि जुडिशियरी के जरिए ही यह तय हो तो अच्छा है, आप खुद इस बात को समझ सकते हैं ।

श्री सैयद अहमद हाशमी : जनाब, जिस इमैलिटैरियन सोसायटी को आप बनाना चाहते हैं, जिसमें बराबरी का एक ही हिसाब मिले और इंडियन जुडिशल सर्विस जिसका कांसेप्शन है कि आप सब को इंसाफ देना चाहते हैं तो उसमें इसका लिहाज रखा जाएगा कि उसमें गरीब लोग भी आ सकें या फ्यूडल सोसायटी, कैपिटलिस्ट सोसायटी, अमीर तबके के लोग ही उसमें पार्टिसिपैट करें ? उसमें गरीब लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो सकेगा जो कि 80 परसेंट हैं । जब तक आप उनको रिजर्वेशन नहीं करेंगे तब तक वे कैसे आ सकेंगे ? मैं जानता हूं कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो सकता । आपके जो क्रिमिनल लाज हैं उनके अन्दर भी

देखिए तो नतीजा यह होता है कि वह तबके मुतमईन नहीं हो पाते क्योंकि उनका प्रापर रिप्रजन्टेशन नहीं है ।

†[شری سید احمد ہاشمی : جناب-

جسر ایجوڈیکیٹوریل سوسائٹی کو آپ بڑھانا چاہتے ہوں - جسر میں برابری کا ہو ایک کو حساب دے اور انڈین جوڈیشیول سروس جس کا کانسٹیٹیوشن ہے کہ آپ سب کو انصاف دینا چاہتے ہیں تو اس میں اس کا لحاظ رکھا جائیگا کہ اس میں غریب لوگ بھی آسکیں یا فیوڈل سوسائٹی کوپیٹالسٹ سوسائٹی اوپر طبقے کے لوگ ہی اس میں پارٹی سپیٹ کریں - اس میں غریب لوگوں کا پارٹی سپیشن کیسے ہو سکے گا جو کہ ۸۰ پرسنٹ ہوں - جب تک آپ ان کو ریزرویشن نہیں کرینگے تب تک وہ کیسے آسکینگے - میں جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو سکتا - آپ کے جو کرمچاری ہیں ان کے اندر آپ دیکھئے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طبقے مطمئن نہیں ہو پاتے کیونکہ ان کا پراپر ریپرزنٹیشن نہیں ہے -]

श्री हंसराज भारद्वाज : जनाबे वाला, मैं अपने लायक दोस्त से अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक इक्वैलिटी का सवाल है, हमारे कांस्टीट्यूशन में, हमारे आईन में बड़े साफ तौर पर इक्वैलिटी दी जा चुकी है । उसको कोई न समझे तो यह मेरा कसूर नहीं है । जहां पर कोर्टस का ताल्लुक है, यह भी सबको मालूम है कि हमारे हिन्दुस्तान के लोगों के लिए सब कोर्टों के दरवाजे खुले हुए हैं । जहां तक यह बात कि उसका टिल्ट गरीबों के हक में नहीं है, अमीरों के हक में है, उसके बारे में खुद हाशमी साहब जानते हैं । हम पूरी ताकत के साथ कानून में सुधार लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं । . . . (व्यवधान)

आप मेरी बात तो सुनिए । मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप जानते हैं कि इस सिलसिले को जो कानून का सिलसिला है, जुडिशियरी का सिलसिला है इसको समझना, इसको बदलना और इसको बार-बार बदलना इतना आसान काम नहीं है लेकिन आप इस बात से बिल्कुल मुतफिक होंगे कि आज जो हमने शुरुआत की है गरीबों को लीगल एड देने की यह पिछले 4–5 साल पहले नहीं थी, दे रहे है और ज्यादा देंगे और गरीबों के हक में हमारी गवर्नमेंट ने जो कदम उठाये हैं वे पहले नहीं उठाये गये । हम गरीबों के हक में कानून को झुका कर छोड़ेंगे ।

SHRI S.W. DHABE : Sir, the question is that unless the quality of judicial service is improved, justice will not be given to the people of this country. The problem is that cost is going up. The question of abolition of court fee is still there. There are no mobile courts, except Lok Adalats or the Legal Aid Committees. May I know from the hon. Minister whether he will examine the question of making justice cheaper by abolition of court fees and also have mobile courts at the village level so that the people need not go 50 miles or come to Delhi to get justice ?

SHRI ASOKE KUMAR SEN : The two questions are different. Court fees have been sought to be regularised or rationalised. That is still under consideration by the Government. So far as mobile courts are concerned, it throws up a lot of problems. First of all, there is the problem of a secretariat, problem of attendance, and various other problems. But we are trying to move in that direction as far as possible, and that was one of the suggestions made by the joint conference. As it is, it is difficult to accommodate the people in the existing courts and when they come to the maidan it will be a very difficult matter. So

†[ ] Transliteration in Arabic script.

many things have to be considered. But the move is to take the courts nearer to the people.

SHRI ALADI ARUNA *alia* V. ARUNACHALAM : Sir, the hon. Minister is aware of the fact that any new All India Service, including the Indian Judicial Service, will amount to transgressing into the judiciaries of the States and it has been strongly opposed by most of the State Governments earlier. That is why, during the Janata party period, I think an assurance was given on behalf of the Government that no new All India Judicial Service will be introdued. In view of this will this Government come forward to scrap this.....

MR. CHAIRMAN : The Minister has understood you.

SHRI ASOKE KUMAR SEN : It is quite true that about 8 States opposed it. But I think the change of events and forced circumstances have now impressed upon the State Governments to have a second look at the concept. It is true, as the hon. Minister of State has said, we are not trying to impose any judicial service on the States but we are trying to carry the States with us for the purpose of constituting a more effective and effcient service.

MR. CHAIRMAN : Shri Virendra Verma.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह इस पक्ष में हैं कि आल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाए। माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिसेज चाहे सुप्रीम कोर्ट में हों या हाई कोर्ट के हों और मुख्य मंत्री भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं इस सम्बन्ध में तो जब भी उनसे पूछा गया था, पहले भी पूछा था और अब भी नैसेसरी है उनसे पूछा जाना तो इस संबंध में उन्होंने उनसे क्यों पूछताछ नहीं की ? इस का क्या कारण था जब कि खुद की दिलचस्पी है कि उनसे पूछा जाना जरूरी है ? बी पार्ट में यह पूछना चाहता हूं कि जहां तक मोबाइल कोर्ट्स का प्रश्न है, एक सुझाव आया था और मंत्री जी ने उत्तर दिया तो क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि मोबाइल कोर्ट्स में जैसा कि आजकल के जजेज की एक आदत बन गई है तारीख पर तारीख देने की। अगर मोबाइल कोर्टस को गांवों में ले जाते हैं और आगे की तारीख दे देते हैं तो वकील लोग गांव वालों से पैसा लेंगे। इससे गांवों के गरीब लोगों पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। क्या इन बातों की आपको जानकारी है ?

श्री हंस राज भारद्वाज : श्रीमान्, जहां तक आल इंडिया जुडिशियल सर्विस का ताल्लुक है, यह प्रश्न कि इस कांफ्रेंस में, इस जौयन्ट कांफ्रेंस में, इस पर क्यों नहीं विचार किया गया, मैं यह निवेदन कर दूं कि फरवरी, 1985 में तमाम चीफ जस्टिसेज की कांफ्रेंस हुई। उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया जो आल इंडिया जुडिशियल सर्विस की मुखालफत का रिजोल्यूशन था। उसके बाद चीफ जस्टिस आफ इंडिया ने इसको एन्डोर्स्ड किया। क्योंकि चीफ जस्टिसेज और चीफ जस्टिस आफ इंडिया ने इसको एन्डोर्स्ड किया था तो जौयन्ट कांफ्रेंस में हमने दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दे जो आल इंडिया जुडिशियल सर्विस से अधिक महत्वपूर्ण थे, उनको लिया और उन पर बहस हुई। उस वक्त इस पर हमने गौर नहीं किया या जैरेगौर नहीं है, यह कहना ठीक नहीं होगा। हमने इसको पोस्टपोन किया। हमने सोचा कि चीफ जस्टिसेज और चीफ जस्टिस आफ इंडिया इंडिविजुअली वार्तालाप करेंगे और उनको कंविन्स करेंग और शायद उम्मीद है कि हमारे मिनिस्टर साहब को उनसे जो रैपर्ट है, उनसे मुहब्बत है, उससे वे उस रिजोल्यूशन को वापस करा देंगे और उनको भी इसके हक में करा दें।

SHRI M. S. GURUPADASWAMY : As a concept, Sir, the creation of an All-India Judicial Service is wrong and dangerous as it

impinges on the jurisdiction and powers of the State Governments and also the jurisdiction and powers of the judiciary in the States. My hon. friend, Mr. Sen. has said that as a consequence of a chain of events, this concept has got to be considred. I take shelter under the same plea. I would like the hon. Minister of Law to appreciate that in the existing circumstances and as a result of a chain of events the State Governments will not agree in general for the creation of a judicial service because we want the judiciary to be free and independent and the creation of a judicial service at the all-India level will certainly give more powers to the executive at the Centre. Therefore, may I ask the hon. Minister to give up this idea of creation of the All-India Judicial Service as it is retrograde, obnoxious and perverse ?

SHRI ASOKE KUMAR SEN : Sir, the hon. Member has only to read the articles in the Constisution starting from 234 onwards to tee that even if a judical service is constituted, the service assigned to the respective States will be under the High Court for their regulation, disciplinary action and various other matters. Therefore, the independence of the judiciary is not going be affected at all. It is a wrong thing to suggest that the States now control the judiciary. It is the State High Courts who do it under the Constitution. The States only appoint and dismiss the judges at the instance of the High Courts. Otherwise the entire control of the judiciary in the States vests, and rightly vest, in the High Courts and it will continue to vest in the High Courts. Perhaps the hon. Member knows better than myself. I am not so sure that the States are not having second look at the matter.

MR. CHAIRMAN : Question No. 2—the hon. Member absent. Q. No. 3.

*2. [*The Questioners (Shrimati Monika Das) and (Shrimati Maimoona Sultan) were absent. For answer* vide *cols.* 40-41 infra]

Recommendations of The Joint Meeting of Chief Justices, Chief Ministers and Law Ministers

*3. SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA : †
SHRI SURESH PACHOURI :

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a joint meeting of the Chief Justices, Chief Ministers and Law Ministers was held in New Delhi on 31st August, 1985 ;

(b) if so, what were the main issue discussed and what decisions were taken or recommendations made in the meeting ; and

(c) what is the reaction of Government thereto and what steps are being taken by Government to implement them ?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI ASHOKE KUMAR SEN) : (a) Yes, Sir. It was held on 31st August and 1st September, 1985.

(b) Statement I containing the agenda for the Conference is placed on the Table of the House.

Statement II containing the Resolutions adopted in the Conference is placed on the Table of the House.

(c) the Resolutions adopted in the Conference are under examination in consultation with the State Governments, wherever necessary.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Satya Parkash Malaviya.